साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 14-20 नवंबर , 2022, वर्ष-8, अंक-32

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

विभाग के आला अफसरों को ही योजना की जानकारी नहीं

प्रदेश के किसानों को नहीं है कृषि उड़ान योजना की जानकारी

कृषि उत्पादन में आगे, 'उड़ान' में फिसडडी मप्र

-योजना का लाभ लेने में एमपी फिसड्डी व महाराष्ट्र निकला अव्वल

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश आज देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य बना है, लेकिन अपने उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना का उपयोग करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को हर प्रकार की मदद मुहैया करवाने संबंधी विशेष लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की है। देश के किसानों की आय दोगुनी हो सके इसके प्रति केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए आ रही समस्याओं को लेकर मोदी सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना 2.0 की शुरुआत की गई है। इस योजना के बाद 53 एयरपोर्ट से किसानों के सामान की आवाजाही शुरू हो जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा कृषि उड़ान योजना पहले भी शुरू की गई है। इसी योजना में नए बदलाव किए गए हैं। योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

किसान नहीं उठा पा रहे फायदा

यहां के किसानों को अपनी फसल को जल्द से जल्द उचित स्थान पर अर्थात मंडी में भेजना होता है, परंतु परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं होने पर फसल खराब होने का डर बना रहता है। अब सरकार द्वारा किसानों को राहत देने के लिए कृषि परिवहन व्यवस्था शुरू की गई है। लेकिन मप्र के किसान इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।

किसानों को जानकारी नहीं

सरकार ने किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसी ही एक योजना का नाम प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की उपज को जल्द से जल्द बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। आंकड़े बता रहे कि मध्यप्रदेश के किसान अपने उत्पादों को एयर ट्रांसपोर्ट करने में कई राज्यों से काफी पीछे हैं जबकि ,प्रदेश उद्यानिकी की कई फसलों के उत्पादन में देश में टॉप फाइव पर है। इसका बड़ा कारण सामने आया है कि विभाग के आला अफसरों को ही इस योजना की जानकारी नहीं है।

महाराष्ट्र निकला आगे

कृषि उड़ान योजना के अन्तर्गत किसानों की फसलों को विशेष हवाई जहाज के जरिये समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाना है। योजना में आठ मंत्रालय नागर विमानन, कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, वाणिज्य विभाग, जनजातीय कार्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास आदि शामिल हैं। योजना के अन्तर्गत जनवरी 2021 से जून 2022 तक जल्द खराब होने वाले उत्पादों का कार्गो डिटेल सामने आया है कि इसमें प्रदेश से महज 859 मीट्रिक टन उत्पादन का व्यापार हुआ। महाराष्ट्र सबसे आगे है।

मुरैना में तीन दिवसीय कृषि मेला और प्रदर्शनी का किया शुभारंभ, बोले सीएम

मप्र में नरवाई से बनेगा भूसा

» सीएम ने कहा-किसानों की आय को दोगुना करने उत्पादन भी बढ़ाएंगे

» केंद्रीय मंत्री तोमर बोले-नई कृषि टेक्नोलॉजी से किसान अपने आपको करें मजबूत

भोपाल। जागत गांव हमार

पीएम मोदी के किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प की सिद्धि के लिए उत्पादन भी बढ़ाना होगा और लागत को कम करना होगा। इस दिशा में मप्र सरकार जहां एक ओर सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ा रही है। वहीं किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों के लिए कृषि मेला भाग्यविधाता साबित होगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना जिले में तीन दिवसीय कृषि मेला एवं प्रदर्शनी के शुभारंभ के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों द्वारा नरवाई को जलाने की प्रथा को खत्म करने के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है। योजना में मशीन द्वारा नरवई से भूसा तैयार किया जाएगा। मशीन खरीदने के लिए छोटे किसानों को 50 प्रतिशत और बड़े किसानों को 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। नरवई से तैयार भूसा गौ-माता के काम आएगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। हर 10 से 20 गांव के बीच केंद्र बनाएंगे। साथ ही कस्टम हायरिंग सेंटर का भी निर्माण होगा।

10 हजार मिल रही सम्मान निधि

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों को आर्थिक मदद के लिए जहां एक ओर प्रधानमंत्री एक साल में तीन किस्तों में 6 हजार देते हैं। वहीं मध्यप्रदेश सरकार भी अपनी ओर से इन किसानों को साल में 2 किस्तों में 4 हजार दे रही है। इस प्रकार किसान को एक साल में 10 हजार की सहायता मिल रही है। प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी अब तक 2 लाख 12 हजार करोड़ मिल चुके हैं।

किसानों को मिला संबल

मप्र में फसल बीमा योजना में किसानों के खातों में 7618 करोड़ डाले गए हैं। इतनी बड़ी राशि किसी राज्य के किसानों को नहीं मिली। पीएम ने गेहूं का समर्थन मूल्य भी 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर किसानों को संबल दिया है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अनेक नवाचार के साथ नई कृषि तकनीक भी अपनाई जा रही है। ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जा रही हैं। कांग्रेस की सरकार के समय नहरों से पानी टेल एंड तक नहीं पहुंचता था। हमने नहरों को पक्का बना कर टेल एंड तक पानी पहुंचाया है।

उद्यानिकी फसलें भी लें

प्रदेश के उद्यानिकी प्र-संस्करण एवं जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना है। प्रदेश लगातार पिछले 6 वर्षों से केन्द्र सरकार की ओर से कृषि के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर रहा है। प्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में लगातार नए-नए आयाम एवं नवाचार कर रही है। किसान रबी एवं खरीफ फसलों के साथ उद्यानिकी फसलें भी लें, जिससे खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त हो सके।

नवाचारों से खेती को बना रहे लाभकारी

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री गांव के विकास और खेती को लाभकारी बनाने के लिए अनेक नवाचार कर रहे हैं। फसल बीमा सुरक्षा के साथ किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ दिया जा रहा है। मप्र कभी बीमारू राज्य कहा जाता था। शिवराज के नेतृत्व में प्रदेश के हर गांव और हर शहर का विकास हो रहा है। प्रदेश की कृषि विकास दर में बढ़ोतरी हुई है। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। सिंचाई का क्षेत्र लगातार बढ़ने का लाभ भी सीधे किसानों को मिल रहा है।

मछुआरों के अच्छे दिन | शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

मछली पालकों को आत्म निर्भर बनाएंगे फिश पार्लर

-बैठक में मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना को भी मंजूरी दी गई

-किसानों को कृषि यंत्र खरीदी पर 50 फीसदी मिलेगी छूट

-राशन दुकानों पर कमीशन अब 90 रुपए क्विंटल मिलेगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार अब मछुआ समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है।

मध्यप्रदेश के बड़े शहरों से लेकर जिला स्तर पर फिश पार्लर बनाए जाएंगे। इन फिश पार्लरों में डीप फ्रीजर से लेकर मछली को हाईजीनिक तरीके से छीलने और काटने की मशीनरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री मछली मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत मछली पालकों को बढ़ावा देने के लिए सौ करोड़ की मंजूरी दी गई। मप्र सरकार के प्रवक्ता डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को मंजूरी दी गई। राशन की सप्लाई का काम प्रायवेट ठेकेदारों के बजाए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लाभ दिया जाएगा। इन बेरोजगार युवाओं को लोन और गाड़ी दिलाकर ब्याज की व्यवस्था की जाएगी। पहले चरण में 888 युवाओं को लाभ मिलेगा।

पंचायतों में खुलेंगी नई राशन दुकान

जिन पंचायतों में राशन दुकान नहीं हैं वहां नई दुकान खोलने के लिए 1514 दुकानों को 6 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। पीओएस अतिरिक्त मार्जिन की राशि 17 क्विंटल से बढ़ाकर 21 प्रति क्विंटल की गई है। 50 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त 52.20 करोड़ प्रतिमाह इस पर खर्च करने की मंजूरी दी गई।

किसानों को 50 फीसदी मिलेगी छूट

नरवाई को रोजगार से जोड़ने का तय किया है। नरवाई से भूसा बनाने के लिए बड़े किसानों को छोड़कर सभी किसानों मशीन के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। गौशालाओं को भी नरवाई से भूसा बनाने वाली मशीन पर 40 फीसदी छूट मिलेगी। कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाने के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई।

सतत कृषि तकनीक का विकास और विस्तार ने अन्नदाताओं में एक जागृति हो चुकी पैदा

फसल विविधीकरण से बढ़ेगी आमदनी

भोपाल। जागत गांव हमार

बढ़ती जनसंख्या शहरीकरण के फैलते विस्तार के कारण कृषि में विविधीकरण आज की महती आवश्यकता बनकर उभरी है। उल्लेखनीय है कि कृषि एवं कृषि से जुड़े व्यवसाय के भरोसे टिकी 67 से 70 प्रतिशत आवाम को अब जीने के लिए कृषि के पुराने तर्ज छोड़कर नए तौर-तरीकों को अपनाकर आर्थिक उत्थान किया जाना ही एकमात्र मार्ग बचा है। कृषि विविधीकरण खेती के पारम्परिक तरीकों को बदलकर नए तरीकों का अंगीकरण यथासंभव जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, जो साठ वर्ष पहले होता था। खरीफ अथवा रबी की एक फसल भूमि, जलवायु, वर्षा की परख करके लगाना और काटना बस, परंतु आज इतने से काम चलना संभव नहीं है। आज पारम्परिक फसलों की जगह मुनाफे वाली फसलें जैसे मसाला फसलें, औषधि फसलें, फूल एवं फलों की खेती का समावेश कुछ रकबे में किया जाना जरूरी हो गया है। खेती के साथ खेती से प्राप्त बेशुमार कीमती अवशेषों का समुचित उपयोग भी इस पद्धति का उद्देश्य है खेती के साथ पशुपालन तो मानो सदियों से जुड़ा एक अहम कार्य है। बीच में मशीनीकरण के चलते जरूर इस दिशा में कुछ शिथिलता आई थी वह भी जैविक खेती की संजीवनी के साथ पुनः वापस आने लगी है। मशरूम पालन बिल्कुल कम लागत में खेत के एक कोने में किया जाना संभव है तो मधुमक्खी पालन के लिए खुले में पड़ी थोड़ी सी भूमि का सद्उपयोग किया जा सकता है।

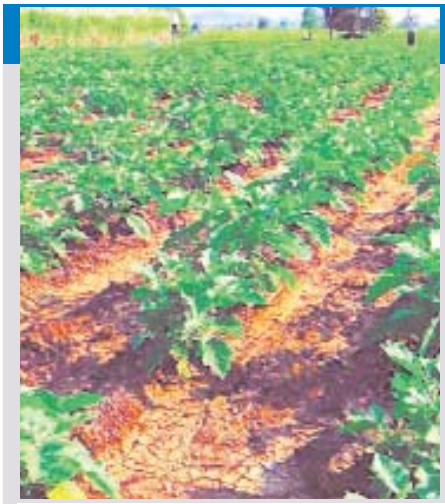

किसानों की बढ़ जाएगी आमदनी

सभी कार्यों के संचालन के लिए शासन द्वारा विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर प्रशिक्षण मुफ्त प्राप्त करने की सहूलियत भी है यही कारण है कि व्यवसायिक फसलों एवं अन्य कृषि से जुड़े व्यवसायों की ओर विविधीकरण का विचार ना केवल हमारे देश में बल्कि सभी विकासशील देशों के लिए एक आवश्यकता बन कर उभरा है। ताकि कृषि आमदनी में बढ़ोत्तरी की जाकर एकल फसल उत्पादन के खतरे से भी बचा जा सके। अमूमन देखा गया है कि मानसून के मिजाज में वर्तमान में भारी परिवर्तन हो रहे हैं। उससे निपटने के लिए कृषि में यदि विविधीकरण का विस्तार हो जाये तो मानसून द्वारा प्रायोजित खतरों से सरलता से निपटा जा सकता है।

दूर हो जाएगी भुखमरी

गरीबी और भुखमरी से भी पीछा छुड़ाया जा सकता है। खाद्यान्न फसलें गेहूं, धान में हरितक्रांति प्राप्त करने के बाद से कृषि विविधीकरण ने जोर पकड़ा है सतत कृषि तकनीक का विकास और विस्तार ने कृषकों में एक जागृति पैदा हो चुकी है और वे परम्परागत फसलों के स्थान पर फल/सब्जियां, फूल तथा मशरूम उत्पादन में विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। इस विविधीकरण क्रिया को गति देने में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का हाथ नकारा नहीं जा सकता है।

नाबार्ड भी दे रहा योगदान

देश की नाबार्ड जैसी संस्थान का योगदान कृषि क्षेत्र में विविधीकरण लाने के लिए एक मील के पत्थर जैसा याद किया जाएगा। जिसमें कृषकों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना भी शामिल है। इन सभी प्रयासों के सुखद परिणाम सामने हैं। 50 के दशक में जो अखाद्यान्न फसलों का रकबा था में करीब 10 प्रतिशत तक की वृद्धि आंकी गई है। देश में खेती योग्य भूमि को बढ़ाना असंभव है परंतु अन्य संसाधन जैसे विशाल समुद्रीय तटों पर मछली पालन, फल/फूल का प्रोसेसिंग आदि नवीन कार्यों को हाथ में लेकर इस दिशा में प्रगति करने की अपार सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

दिव्यांशी अपनी कविताओं से बाल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी

रीवा की छात्रा दिव्यांशी का यूनिसेफ आगाज एलुमनाई इंटर्नशिप 2022 के लिए चयन

रीवा। जागत गांव हमार

राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय रीवा की छात्रा दिव्यांशी सिंह का चयन यूनिसेफ आगाज एलुमनाई इंटर्नशिप 2022 के लिए हुआ है। दिव्यांशी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की सक्रिय स्वयंसेविका है, 2021 में भी इनका चयन यूनिसेफकिशोर एवं युवा इंटर्नशिप के लिए हुआ था। जिसमें मप्र के सभी जिलों से बाल संरक्षण प्रतिनिधि के रूप में 230 स्वयंसेवकों का चयन हुआ था, जिसमें से रीवा जिले से दिव्यांशी का चयन हुआ था। इंटर्नशिप के दौरान छात्रा ने विभिन्न नवाचार जैसे रंगोली, पोस्टर, जनसंपर्क, कविताओं इत्यादि के माध्यम से बाल संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता फैलाई थी और इंटर्नशिप के लिए इन्हें 20000 भी प्राप्त हुए थे। वर्ष 2022 में आगाज का सीजन -2, आगाज एलुमिनाई आया। जिसमें 2021 के चयनित 230 प्रतिभागियों से आवेदन मांगे गए थे, जिसमें से केवल 50 छात्रों का चयन हुआ है। 50 छात्रों में सातवें नंबर पर रीवा की दिव्यांशी का चयन हुआ है। दिव्यांशी अपनी कविताओं के माध्यम से बाल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी। कृषि कालेज रीवा के अधिष्ठाता डॉ एस. के. पयासी, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ मनीषा मिश्रा, डॉ ए. एस. चौहान, डा आई एम खान, डा आर के तिवारी, डॉ अखिलेश कुमार एवं कालेज के सभी प्रोफेसरों ने दिव्यांशी के उज्जवल भविष्य की कामना की।

खोखम गांव में कृषक प्रशिक्षण

रीवा। कृषि विज्ञान केंद्र रीवा मप्र के प्रमुख डा. ए के पांडेय के निर्देशन में ग्राम खोखम में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्र के पौध संरक्षण वैज्ञानिक डा अखिलेश कुमार और डा स्मिता सिंह द्वारा रबी की फसलों में उत्तम बीज का चुनाव, समय पर बुवाई, संतुलित खाद का प्रयोग, उचित सिंचाई प्रबंधन, बीज उपचार, प्याज और सब्जियों की पौधशाला में प्रबंधन, समन्वित कीट एवम रोग प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन, स्वच्छता प्रबंधन के साथ साथ खरीफकी फसलों में कटाई एवम भंडारण प्रबंधन पर कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। कृषकों को पराली न जलाने के लिए समझाइश दी गई और पराली से डिकंपोजर के माध्यम खाद बनाने के लिए बताया गया। इस अवसर गांव की प्रगतशील कृषक उपस्थित थे।

प्राध्यापकों ने किया रावे कार्यक्रम का निरीक्षण

रीवा। प्रो एस के पयासी के मार्गदर्शन में कृषि महाविद्यालय रीवा चलाए जा रहे ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (रावे) कृषि महाविद्यालय के अंतर्गत कार्य करने वाले केवीके में छात्र छात्राओं द्वारा कृषकों को नई नई तकनीकियों से अवगत कराने के साथ साथ कृषकों द्वारा साझा किया गया। रावे के इंचार्ज एवं विभागाधयक्ष कृषि विस्तार विभाग, प्रो ए एस चौहान एवं डा अखिलेश कुमार विभागाध्यक्ष कीट विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय रीवा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र सीधी मप्र गए छात्राओं के ग्राम चौपाल कोठार सीधी म प्र कृषकों के बीच किए जा रहे क्रियाकलापों का निरीक्षण किया गया। वैज्ञानिक दल किसानों की समस्याओं से हुआ। आगामी रबी की फसलों में आने वाली समस्याओं पर कृषकों के बीच

समय पर करें बिजाई, मिलेगा उम्मीद से बढ़कर लाभ

गन्ने की फसल से 30 फीसदी अधिक पैदावार पाने अपनाएं यह विधि

भोपाल। जागत गांव हमार

देश के किसानों के लिए गन्ना मुख्य नकदी फसल में से एक है। इसकी खेती से किसानों को डबल मुनाफा होता है, क्योंकि यह देश में चीनी का एक मात्र मुख्य स्त्रोत है। इसी कारण से किसान गन्ने के सीजन (अक्टूबर-नवम्बर) में इसकी खेती सबसे अधिक करते हैं। अगर किसान अपने खेत से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए गन्ने की खेती करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। गौरतलब है कि दुनियाभर में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि अकेले भारत में गन्ने की फसल की अनुमानित उत्पादकता 77.6 टन प्रति हेक्टेयर और वहीं उत्पादन क्षमता लगभग 306 मिलियन टन होती है। संभवत: गन्ने की खेती हर एक किसान करता है, लेकिन अच्छा मुनाफा उसे ही प्राप्त होता है, जो इसकी खेती की अच्छी और उन्नत तरीके की विधि से खेती करता है। आप भी गन्ने की उन्नत विधि को अपनाकर अपने खेत में गन्ने की बिजाई करें जिससे आपको भी डबल लाभ प्राप्त हो सके।

ट्रेंच विधि या फिर गड्ढा विधि

अगर आप गन्ने की फसल से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके को अपनाकर लगभग 30 प्रतिशत से अधिक गन्ने की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि के लिए आपको अधिक कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती है। यह एक परम्परागत विधि है, जिसमें पानी की मात्रा बेहद कम लगती है। इस विधि के द्वारा खरपतवार कम और खाद का सही इस्तेमाल होता है। इसमें आपको खेत में गन्ने की बिजाई करने के लिए लगभग 1 फीट गहरी 1 फीट चौड़ी नालियों को तैयार करना होता है। इसके बाद इन नालियों में कम से कम 25 सेमी लंबे 2 से 3 आंख वाले गन्ने लगाए जाते हैं। आप गन्ने की खेती करने का सोच रहे हैं तो ऐसे में आप गन्ने की इन किस्मों की खेती कर अच्छे उत्पादन के साथ अच्छा मुनाफा भी पा सकते हैं। इस विधि में गन्ने से गन्ने की दूरी 10 सेमी और नालियों की दूरी 4 फीट तक होनी चाहिए। इस विधि की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप एक साथ दो फसल की खेती कर सकते हैं। किसान खेत में गन्ने के साथ दूसरी दलहनी फसल भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से किसान को डबल मुनाफा तो होगा ही साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी होगी।

सही मात्रा में डालें खाद, ताकि अच्छी रहे फसल

अगर किसान अपने खेत में ट्रेंच विधि या फिर गड्ढा विधि से गन्ने की खेती करते हैं, तो आपको एक एकड़ खेत के लिए लगभग 80 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश डालना चाहिए। ध्यान रहे कि बोवनी के समय आपको फसल में नाइट्रोजन का तीसरा हिस्सा डालना है। ताकि फसल अच्छे से तैयार हो सके।

भोपाल जिले में किसानों ने रबी फसल बोने के लिए तैयारी शुरू कर दी

खाद को लेकर किसान परेशान, प्रशासन ने कहा संकट नहीं

भोपाल। जागत गांव हमार

जिले में किसानों ने रबी फसल बोने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं किसानों ने सोसायटी से खाद लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों के सुस्त रवैए के चलते किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ता है। वहीं प्रशासन का दावा है कि खाद का कोई संकट नहीं है, पर्याप्त खाद है। किसान समय रहते खाद ले सकते हैं। किसान रामबाबू ने बताया कि उनको एक हेक्टेयर पर सिर्फ पांच बोरी खाद दिया गया है। जबकि उनकी मां के नाम से जमीन है जिनकी उम्र 60 से ज्यादा हो गई है इस वजह से सोसायटी से खाद देने से मना कर दिया है। वहीं किसान हजारीलाल ने बताया कि यूरिया नहीं दिया जा रहा है वहीं डीएपी भी कम बोरी दे रहे हैं। इससे समय पर खाद नहीं मिला तो फसल बोने में समस्या आएगी।

शासन ने बताई खाद पर्याप्त

भोपाल जिले में यूरिया सहित उर्वरक उपलब्ध है और किसी तरह का संकट नहीं है। उप संचालक कृषि भोपाल जिले में अब तक वितरित और उपलब्ध खाद तथा उर्वरक की जानकारी दी है। उप संचालक ने बताया कि जिले में यूरिया 5004 मिट्रिक टन, डीएपी 4273 मिट्रिक टन एनपीके 1284 मिट्रिक टन तथा डीएपी प्लस एनपीके 5558 मिट्रिक टन उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अब कि अब तक जिले में 25020 मिट्रिक टन यूरिया, 14353 मिट्रिक टन डीएपी, 1180 मिट्रिक टन एनपीके और डीएपी प्लस एनपीके 15533 मिट्रिक टन विक्रय की गई है। उपसंचालक कृषि ने बताया कि गत वर्ष इसी अवधि में 32726 मिट्रिक टन यूरिया, 14670 डीएपी, 5954 एनपीके और 20623 मिट्रिक टन डीएपी प्लस एनपीके का विक्रय किया गया था।

पक्का बिल लेने की सलाह

संयुक्त संचालक कृषि बीएल बिलैया ने संभाग के सभी जिलों के कृषकों से आग्रह किया है कि रबी मौसम की बोवनी के दौरान खाद, बीज का क्रय जिन संस्थाओं से करते है, उसका पक्का बिल अवश्य लें। यदि कोई व्यापारी, दुकानदार पक्का बिल देने में आनाकानी करता है अथवा समय पर बिल नहीं देता है तो अविलम्ब इसकी जानकारी स्थानीय एसडीएम के संज्ञान में अवश्य लाएं। ताकि संबंधित विक्रेता के खिलाफ जांच पड़ताल कर कठोर कार्रवाई की जा सके।

खेती में मिलेगा सहारा, नहीं आएगी ज्यादा लागत

रबी सीजन में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं किसान

भोपाल। जागत गांव हमार

रबी फसलों पर सरकान ने एमएसपी भी बढ़ा दी है। रबी सीजन के लिए किसानों ने बोवनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही किसान कुछ सरकारी योजनाओं जैसे फसल बीमा योजना, कृषि विकास योजना का लाभ उठा सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर खेतीबाड़ी में किसानों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि सरकारें भी किसानों और खेती में आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए समय-समय पर कई लाभकारी योजनाएं संचालित करती रहती हैं। इनमें किसानों को खेत-खाद-उर्वरक-मशीनरी आदि से लेकर घर तक की व्यवस्था का प्रयोजन होता है।

सरकार ने फसल को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से राहत के लिए इस योजना का संचालन किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुल बीमा राशि का रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत और खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। वार्षिक या बागवानी फसलों के लिए कुल बीमा राशि का केवल 5 प्रतिशत प्रीमियम ही भुगतान करना होता है। फसल को नुकसान होने की स्थिति में- किसानों को पूरी बीमा राशि मिले, इसके लिए शेष प्रीमियम राशि का पेमेंट सरकार द्वारा ही किया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

सरकार द्वारा किसानों को आसानी से कम ब्याज दर पर खेतीबाड़ी के लिए लोन मुहैया कराने के लिए इस योजना का संचालन किया गया है। इस स्कीम के माध्यम से किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

इस योजना के तहत किसानों को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य मोटे अनाज, मृदा स्वास्थ्य और पशुपालनों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है।

कृषि उड़ान योजना

इस योजना के तहत किसानों कृषि उत्पादन के परिवहन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना से किसानों की फसलों और उनके उत्पादों जैसे दूध, मांस, मछली को सही समय पर बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

2021 के मुकाबले सात गुना ज्यादा मंडी में पहुंची उपज

नवंबर में उपज की आवक का बन गया नया रिकॉर्ड

गुना। जागत गांव हमार

मंडी में इस साल रिकॉर्ड तोड़ आवक हो रही है। अकेले नवंबर माह के दौरान तीन लाख क्विंटल से ज्यादा विभिन्न उपज की डाक हो चुकी है। 2021 में इसी अवधि के मुकाबले यह करीब 7 गुना ज्यादा है। एक दिन तो 55 हजार क्विंटल आवक दर्ज की गई। वहीं अगले दिन आवक का आंकड़ा 50 हजार तक पहुंचा था। दोनों बार मंडी परिसर में जगह न बचने के कारण ट्रॉलियों को दशहरा मैदान पहुंचा गया। मंडी सचिव उदय भानु चतुर्वेदी ने बताया कि 2021 में नवंबर माह के पहले हफ्ते के दौरान 40 हजार क्विंटल आवक हुई थी। इस बार यह 3 लाख के पार पहुंच गई। तीन लाख क्विंटल में अकेले मक्का की हिस्सेदारी 1.40 लाख क्विंटल है। यानि करीब-करीब 50 फीसदी। दूसरा नंबर गेहूं का रहा, जिसकी आवक 22 हजार क्विंटल रही। जबकि यह सीजन की फसल नहीं है। वहीं सीजन की सबसे अहम फसल सोयाबीन महज 10 हजार क्विंटल तक ही पहुंची। इसी तरह दूसरी ऑफ सीजन वाली फसल सरसो की आवक भी पिछले साल 168 के मुकाबले 2213 क्विंटल रही।

खासियत जानकर किसान रह जाएंगे दंग

वैज्ञानिकों ने विकसित की चने की नई किस्म

भोपाल। जागत गांव हमार

अभी रबी फसल की बोवनी चल रही है। वहीं, कई किसानों ने गेहूं और जौ सहित अन्य फसलों की बोवनी कर दी है, लेकिन कई ऐसे भी किसान हैं, जो अभी तक अपनी पूरी जमीन पर रबी फसलों की बोवनी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में इन किसानों के लिए अभी चने की बोवनी करने के लिए अच्छा मौका है। दरअसल, मार्केट में चने की एक नई किस्म आई है। इस नई किस्म की खासियत है कि कम लागत में ही बंपर पैदावार होता है। ऐसे में किसान इस नई किस्म के चने की खेती कर मालामाल हो सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर महीने में चने की बुवाई की जाती है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान तो दिसंबर महीने तक भी चने की बोवनी करते हैं। ऐसे में यहां के किसानों के लिए अभी बेहतर मौका है। वैज्ञानिकों ने चने की एक नई किस्म विकसित कर ली है. इस किस्म की खासियत है कि इसके झाड़ काफी लंबे होते हैं। साथ ही उत्पादन भी सामान्य चने की किस्म के मुकाबले ज्यादा होगा। ऐसे में किसान इसे बेचकर मालामाल हो सकते हैं। खास बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इस नई किस्म का नाम जवाहर चना 24 दिया है।

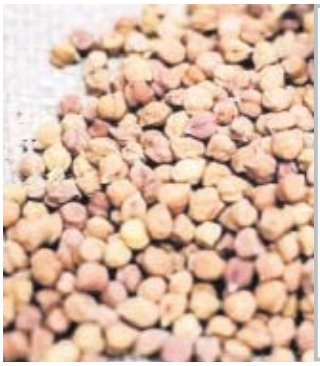

फसलों की बर्बादी भी कम होगी

जवाहर चना 24 के झाड़ को हार्वेस्टर मशीन के माध्यम से भी काटा जा सकता है। ऐसे में किसानों को अब इसकी कटाई की टेंशन भी नहीं रही। पहले जहां चने की कटाई करने में किसानों को एक दिन लग जाता था। वहीं, अब इस नई किस्म के चने को कुछ ही घंटे में हार्वेस्टर मशीन के द्वारा काटा जा सकता है। ऐसे में किसानों को मजदूरों पर होने वाले खर्च से भी राहत मिलेगी। साथ ही फसलों की बर्बादी भी कम होगी।

हार्वेस्टर से होगी कटाई

जवाहर चना 24 को जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जवाहर चना 24 की कटाई हार्वेस्टर के माध्यम से भी की जा सकेगी।

हम काफी लंबे समय से चने की इस नई किस्म पर काम कर रहे हैं। अमूमन चने के झाड़ की लंबाई 45 से 50 सेंमी तक होती है, लेकिन जवाहर चना 24 की ऊंचाई 65 सेंमी तक होगी। साथ ही यह किस्म 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे का तना भी मजबूत होता है। ऐसे में इसे तेजी आंधी से गिरने का डर भी नहीं है।

डॉ. अनिता बब्बर, प्रभारी, अखिल भारतीय चना समन्वित परियोजना, जबलपुर

किसानों के सशक्तिकरण के लिये संकल्पित शिव-राज

कमल पटेल
कृषि मंत्री, मप्र शासन

धरती पुत्र शिवराज सिंह चौहान ने जबसे प्रदेश की कमान सम्हाली है, तभी से स्वर्णिम मप्र के सपने को साकार करने में हर पल गुजरा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में किसान की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसी सोच के मद्देनजर किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये निरंतर कार्य किये हैं, जो आज भी बदस्तूर जारी हैं। अपनी स्थापना के 67वें वर्ष में मप्र कृषि के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश है, जिसने कई कीर्तिमान रचते हुए लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त किया है।

प्रदेश आज विकसित राज्यों की दौड़ में शामिल है। गहूं उत्पादन के साथ ही उपार्जन में भी हम अव्वल हैं। हमने पंजाब जैसे राज्यों को पीछे कर बता भी दिया है और जता भी दिया है कि प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री चौहान के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करने को दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। गुणवत्ता में भी हम सबसे मुकाबला करने को तत्पर हैं। राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाएं, कुशल और सक्षम नेतृत्व, वैज्ञानिकों के साथ ही किसानों की मेहनत का सुफ्ल है कि प्रदेश की रायसेन मण्डी में धान समर्थन मूल्य से 1200 रूपये अधिक तक बिक रहा है। सरकार सतत प्रयास कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का दोगुना से ज्यादा लाभ मिले।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से जनता को लाभान्वित करने में मध्यप्रदेश प्रथम पयदान पर है। उक्त योजना का लाभ देश में सबसे पहले हरदा जिले के किसान रामभरोस विश्वकर्मा को मिला। प्रदेश कृषि अधो-संरचना निधि के उपयोग में भी देश में अव्वल है। प्रदेश में इस निधि से 1508 प्रकरण में 852 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है, जो देश में अब तक किये गये व्यय की कुल 45 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 2-2 हजार रूपये की दो किश्तें प्रदान की जा रही हैं। अब तक प्रदेश के 80 लाख किसानों को 4751 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सबसे अधिक किसानों को लाभान्वित करने वाला राज्य है। योजना में रबी 2020-21 में ही 49 लाख किसानों को 7618 करोड़ रूपये की दावा राशि का भुगतान किया गया।

सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभान्वित करने के लिये वन ग्रामों को भी योजना में शामिल करना, फसल अधिसूचित करने के लिये न्यूनतम सीमा 100 के स्थान पर 50 हेक्टेयर करना, क्षति आकलन के लिये बीमा पोर्टल को लेण्ड रिकॉर्ड के एनआईसी पोर्टल से लिंक करना, अवकाश के दिनों में भी बैंक खुलवा कर किसानों का बीमा कराना और बीमा कव्हरेज के स्केल ऑफ फायनेंस को 100 प्रतिशत तक करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सिंचाई सुविधाओं में अकल्पनीय विस्तार हुआ है। आज प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का रकबा लगभग 45 लाख हेक्टेयर तक पहुँच चुका है। वर्ष 2025 तक इसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। प्रदेश जैविक खेती में पहले स्थान पर है। गुड गवर्नेंस इण्डेक्स 2021 में कृषि संबद्ध क्षेत्र में मध्यप्रदेश नम्बर वन है। कृषि विकास के लिये प्रदेश में ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक पर काम हो रहा है। इसके लिये कृषि क्षेत्र में आधुनिक एवं उन्नत तकनीकों के प्रयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया (एकार्डा) की मदद ली जा रही है। एम-पोर्टल से एसएमएस द्वारा कृषि संबंधी सलाह किसानों को दी जा रही है। प्रदेश में बीज, उर्वरक, कीटनाशक लायसेंस प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है।

प्रदेश में किसानों के हित में निणज्य लिया जाकर अब गेहूँ के साथ ही मूंग, चना, उड़द और मसूर जैसी दलहन और सोया, सरसों जैसी तिलहन का भी उपार्जन किया जा रहा है। सरकार किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन भी कर रही है। इन सबसे किसानों के आथिज्क सशक्तिकरण का मागज खुला है। सरकार ने फसलों के आने के साथ ही उपार्जन से किसानों को उपज का वाजिब दाम मिलना सुनिश्चित किया है। किसान आधुनिक तकनीक से लैस हो रहे हैं।

प्रदेश में ग्रीष्मकालीन फसलों के लिये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त प्रयास किये जा रहे हैं। इसकी बदौलत ग्रीष्मकालीन फसलों के रकबे में 3 गुना तक की वृद्धि हुई है। आज ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल का रकबा बढ़ कर 7 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये प्राकृतिक कृषि बोर्ड गठित किया गया है। प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों में जैविक/प्राकृतिक कृषि शाखाएं प्रारंभ की गई हैं। किसानों को फसल तकनीकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिये कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषि ओपीडी की स्थापना की गई है, जहाँ से कृषक व्हाटसअप और आईटी से कृषि वैज्ञानिकों से सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। सरकार ने किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिये किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केन्द्र (दूरभाष क्रमांक 0755-2558823) की स्थापना भी की है।

पशुओं को स्वस्थ रखने पशु आहार को संक्रमित होने से बचाएं

» डॉ. आफरीन खान
» डॉ. संजू मंडल
» डॉ. चारू शर्मा
» डॉ. दीपिका डी सीजर
» डॉ. अनिल गटटानी
» डॉ. एम हीरा खान
» डॉ. शुभ्रकल नाथ
-पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

इंसानों की तरह ही जानवरों का स्वास्थ्य एवं उनका प्रदर्शन भी संतुलित आहार पर निर्भर करता है पशुपालन में पशुआहार की गुणवत्ता उसकी सफलता का निर्धारण करता है इसीलिए पशु आहार को पशु की नस्ल के अनुसार ही समायोजित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोषण पर्याप्त मात्रा के साथ अवांछित पदार्थों से मुक्त हो, पशु आहार के इस निर्धारण के लिये इनका समय-समय पर विश्लेषण करना चाहिए। पशु आहार को संक्रमित करने वाले पदार्थ को संदूषक कहा जाता है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें पशु आहार में जानबूझकर नहीं जोड़ा जाता है।

पशु आहार में संक्रमित पदार्थ या तो प्राकृतिक स्रोतों से पशु आहार मे मिलते हैं जैसे माईकोटोक्सिन जो कवकों द्वारा उत्पादित होते हैं। अथवा वे संदूषक जो मानव क्रियाओं से पशु आहार में मिल जाते हैं जैसे कारखानों में पशु आहार निर्माण प्रक्रिया।

पशु आहार को संक्रमित करने वाले कारक (संदूषक): प्राकृतिक विषाक्त पदार्थ जो विभिन्न पौधों तथा जीवों द्वारा निर्मित होते हैं जैसे एलकालोइड्स या माईकोटोक्सिन।

पर्यावरण संदूषक एवं भारी धातुएं: पर्यावरण संदूषक मानव निर्मित पदार्थ हैं जो हवा, पानी या मिट्टी में मौजूद होते हैं। इन पदार्थों मे डाईऑक्सिन, क्लोरीनयुक्त कीटनाशक, ब्रोमोनटेड फेनोल एवं अन्य भारी धातुएं जो की पर्यावरण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करती हैं जहां उनकी उपस्थिति या तो प्राकृतिक या औद्योगिक उत्सर्जन से होती है।

सूक्ष्मजीवी संदूषण: उच्च प्रोटीन पशु आहार विशेष रूप से सूक्ष्मजीवी संदूषण से प्रभावित होता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीवी को पनपने के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। संक्रमित चारा पशुओं मे संक्रमण का कारण होता है। पशुधन के मामले मे यह विशेष रूप से समस्या का कारण है क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस संक्रमण के माध्यम से दूध, अंडे तथा मांस में मिल जाते हैं तथा यह पशुओं के साथ-साथ मनुष्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते है।

माईकोटोक्सिन: माईकोटोक्सिन कवकों द्वारा निमिज्त विषाक्त मेटाबोलाइटस् है, यह कवक अनाज को आसानी से संक्रमित कर सकते हैं। माईकोटोक्सिन कम सांद्रता में भी पशुओं में वृद्धि और प्रजनन संबंधी विकार पैदा कर सकते हैं।

पशु आहार को संक्रमित करने वाले कारकों (संदूषकों) पर नियंत्रण: पशु आहार संदूषण की रोकथाम एक जटिल समस्या है जिसका समाधान फसल के उत्पादन से शुरू होकर चारा प्रसंस्करण एवं भंडारण तक होता है। यह सुनिश्चित करने के लिये पोषण- सहित एवं संक्रमित-रहित है हमें कई कदम उठाने होंगे जैसे कि- खाद्य का उत्पादन एवं पैकिजिंग एक सुरक्षित वातावरण में होना चाहिए। परिसर और संरचनाएं जैसे पानी तथा अपशिष्ट का उचित प्रबंधन होना चाहिए। किसानों का व्यक्तिगत एवं उपकरणों की साफ-सफाई होनी चाहिए। कीट- नियंत्रण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसान जानवरों को आमतौर पर पशु आहार के रूप में चारा एवं घास खेत, से ही खिलाते हैं या खेत की फसल को साईलेज जैसे प्रक्रिया से उत्पादित करते है जिसमे के नमी की वजह से सूक्ष्मजीवों एवं कवकों के संक्रमण का खतरा रहता है। ऐसे जीवों से निदान पाने के लिये गर्मी द्वारा आहार का उपचार किया जा सकता है।

पशु आहार संक्रमण के नुकसान: पशु आहार के संक्रमित होने से उसमे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। संक्रमित पशु आहार से पशुओं मे विभिन्न प्रकार के रोगों का संक्रमण हो जाता है। आहार के भंडारण गुणवत्ता में कमी आ जाती है। जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। संक्रमित पशु आहार में उपस्थित विषाक्त मेटाबोलाइट, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है ।

पशु आहार संक्रमण से बचाव: अच्छे गुणवत्ता के ही पशु आहार खरीदें। पशु आहार में सम्मलित सभी घटकों की प्रर्याप्त जानकारी लें द्य यदि पशु आहार मे कोई एंटीबियोटिक मिलाई गई हो तो उसकी भी पूरी जानकारी लें। पशु आहार के साथ, प्रतिबंधित सामग्री की जानकारी अवश्य ले एवं उनका उपयोग भी पशु आहार के साथ न करें। हमेशा पशु आहार को एक साफ़-सुथरे, सूखे कमरे में भण्डार करके रखें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें की वह कमरा चूहे एवं कीटों से मुक्त हो एवं नमीरहित हो, क्योंकि नमी के कारण आहार में कवक संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यदि चारे को साइलेज के रूप मे भण्डार कर रहे हैं तो प्रयोग किए जाने वाली घास एवं फसल उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए एवं साइलेज बनाने की प्रक्रिया में साफ- सफाई का विशेष ध्यान दें। साइलेज बनाते वक्त साइलेज पिट को अच्छे से ढकना एवं सीलबंद करनी चाहिए। यदि पशु चारा किसान स्वयं अपने खेत में उगा रहा हैं तो कीट-नाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए अन्यथा यह उर्वरक और कीटनाशक अवशेष के रूप पशु आहार के माध्यम से पशु शरीर में पहुंच जाएंगे तथा पशु से उत्पादित चीजों को भी संक्रमित करेंगे। जैविक खाद या उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। धूल भी पशु आहार को संक्रमित करते हैं इसलिए चारे को धूल से बचाना बहुत जरूरी है।

बार्टोनेलोसिस, लक्षण और बचाव

» डॉ. बृजमोहन सिंह ठाकड़
» डॉ. रणविजय सिंह
» डॉ. विष्णु गुप्ता
» डॉ. भावना गुप्ता
» डॉ. प्रदीप कुमार सिंह
» डॉ. अजय राय
» डॉ. रश्मि कुलेश
» डॉ. लक्ष्मी यादव

जीनस बार्टोनेला (पूर्व में रोचलिमाइया) के सदस्यों के कारण होने वाले मानव और पशु रोगों के समूह को सामूहिक रूप से बार्टोनेलोसिस कहा जाता है। इसमें कैट-स्क्रैच डिजीज, वैस्कुलोप्रोलिफेरेटिव डिजीज-बेसिलरी एंजियोमैटोसिस, बेसिलरी पेलियोसिस हेपेटाइटिस, बैक्टरेरिया के साथ बुखार को दूर करना, एंडोकार्डिटिस, ग्रैनुलोमेटस हेपेटोस्प्लेनिक सिंड्रोम, रेटिनाइटिस और ऑप्टिक तंत्रिका की सूजन, ऑस्टियोलाइटिक घाव और फुफ्फुसीय ग्रैनुलोमा शामिल हैं। यह भी एड्स एन्सेफैलोपैथी के रोगजनन में जुड़ा हुआ माना गया है। बार्टोनेलोसिस के एटिऑलॉजिकल एजेंट, जिन्हें पहले रोचलिमाई प्रजाति के रूप में नामित किया गया था, 1993 में ब्रेनर और सहकर्मियों द्वारा उनके पुनर्वर्गीकरण के लिए दिए गए औचित्य के आधार पर जीनस - बार्टोनेला के साथ एकजुट थे (ब्रेट्ज़वर्ड, 1995)। तदनुसार, एजेंटों का नाम बी. क्विंटाना, बी. हेंसेले, बी. विंसोनि और बी. एलिजाबेथ रखा गया। **बिल्ली खरोंच रोग (सीएसडी):** यह रोग बी. हेन्सेले के कारण होता है, और इस अध्याय में अन्यत्र विस्तार से वर्णित किया गया है (देखें बिल्ली-खरोंच रोग)। बेसिलरी एंजियोमैटोसिस (एपिथेलॉइड एंजियोमैटोसिस)। यह त्वचा की एक संवहनी प्रोलिफेरेटिव बीमारी है जो कई, रक्त से भरे सिस्टिक ट्यूमर की विशेषता है। रोग, जिसे अब बी. हेनसेले या बी. क्विंटाना के संक्रामक अभिव्यक्तियों के रूप में पहचाना जाता है, को अक्सर प्रतिरक्षात्मक व्यक्तियों में, विशेष रूप से एड्स, तपेदिक या कैंसर के रोगियों में प्रलेखित किया गया है, लेकिन प्रतिरक्षात्मक व्यक्तियों में भी रिपोर्ट किया गया है। हालांकि, यूनाइटेड में बी क्विंटाना प्रेरित बेसिलरी एंजियोमैटोसिस के परिणामस्वरूप संचरण का भंडार और तरीका स्थापित नहीं किया गया है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि बेसिलरी एंजियोमैटोसिस के रोगियों से संबंधित 25-40प्रतिशत स्वस्थ बिल्लियों में, (बी। हेन्सेला बैक्टरेमिया कम से कम 18 महीने की अवधि तक बना रह सकता है। क्या जीनस के सदस्य - बार्टोनेला) रोगजनक हैं बिल्लियों के लिए, निर्धारित किया जाना बाकी है। **बेसिलरी पेलियोसिस हेपेटाइटिस:** जब बेसिलरी एंजियोमैटोसिस में आंत के पैरेन्काइमल अंग शामिल होते हैं, तो स्थिति को बेसिलरी पेलियोसिस हेपेटाइटिस, स्प्लेनिक पेलियोसिस या सिस्टमिक बेसिलरी एंजियोमैटोसिस कहा जाता है। शामिल अंग के आधार पर लगातार या बार-बार आने वाला बुखार: बार्टोनेला संक्रमण की पहचान लगातार या बार-बार आने वाले बुखार, अस्वस्थता, एनोरेक्सिया और वजन घटाने के साथ की जा रही है। बैक्टरेरिया के साथ इस तीव्र ज्वर की बीमारी को प्रतिरक्षात्मक और साथ ही प्रतिरक्षात्मक व्यक्तियों दोनों में प्रलेखित किया गया है, और यह महीनों तक भी रह सकता है। **निदान:** बार्टोनेला संक्रमण का निदान उसी तरह किया जा सकता है जैसा कि बिल्ली-खरोंच रोग के लिए उल्लिखित है। **उपचार** : मानव बार्टोनेला संक्रमण का उपचार बहस का विषय बना हुआ है। मानव सीएसडी रोगियों में रोगाणुरोधी उपचार के प्रति प्रतिक्रिया की स्पष्ट कमी के विपरीत, बेसिलरी एंजियोमैटोसिस, पैरेन्काइमल बेसिलरी पेलियोसिस, और एक्यूट बार्टोनेला बैक्टेरिमिया रोगाणुरोधी उपचार का जवाब देते हैं, विशेष रूप से प्रतिरक्षात्मक व्यक्तियों में। डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और रिफैम्पिसिन को एंटीबायोटिक दवाओं की सिफारिश की जाती है, लेकिन पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, सीप्रोफ्लोक्सासिन और एज़िथ्रोमाइसिन के उपयोग के बाद भी नैदानिक सुधार की सूचना मिली है।

उद्योग के एक वर्ग ने मंजूरी का स्वागत किया, लेकिन दूसरे वर्ग को जीएम सरसों की उपयोगिता पर संदेह

जीएम सरसों पर नास और टास के वैज्ञानिकों में रस्साकशी

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास) और ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (टास) के वैज्ञानिकों ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अगले 10 से 15 दिनों में रबी मौसम में ही नए आनुवांशिक रूप से परिवर्तित संकर किस्म की सरसों डीएमएच-11 के अध्ययन और बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन करने की स्थिति में हो सकती है। दोनों संगठनों ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षण के लिए जीईएसी की मंजूरी के बाद अब और किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और चीजें आसानी से आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि एक आधिकारिक स्पष्टीकरण में बताया गया कि जीईएसी ने मंजूरी दी है, न कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने। नास और टास देश के शीर्ष कृषि वैज्ञानिकों का

प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय हैं जो नीति समर्थन और थिंक टैंक के रूप में भी काम करते हैं। कृषि मंत्रालय के तत्वावधान में आईसीएआर, भारत में कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक शीर्ष निकाय है। इसके तहत 111 संस्थान और 71 विश्वविद्यालय कार्य करते हैं। वर्तमान में भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए बीटी-कॉटन एकमात्र गैर-खाद्य फसल है। नास के अध्यक्ष टी महापात्र ने कहा कि वर्तमान में 10 किलो मदर डीएमएच -11 बीज उपलब्ध है, जिसमें से 2 किलो भरतपुर में आईसीएआर के रैपसीड और सरसों निदेशालय द्वारा पहले ही सोर्स किया जा चुका है।

कंपनियों की मिली-जुली राय

आनुवांशिक रूप से परिवर्तित (जीएम) सरसों के बीज से सीधे प्रभावित होने वाली खाद्य तेल कंपनियों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति द्वारा दी गई परीक्षण की मंजूरी पर मिली-जुली राय व्यक्त की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने मंजूरी का विरोध किया है। वामपंथी झुकाव वाली अखिल भारतीय किसान सभा इसके समर्थन में है। उसने कहा है कि उसका आनुवांशिक परिवर्तन के प्रति विरोध नहीं है, लेकिन वह चाहता है कि इसका परीक्षण भारतीय परिस्थितियों में किया जाए। उद्योग के एक वर्ग ने इस मंजूरी का स्वागत किया है, लेकिन दूसरे वर्ग को जीएम सरसों की उपयोगिता पर संदेह है और उन्हें लगता है कि इससे तेल प्रसंस्करण इकाइयों और छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा।

हरा चारा अधिक होने पर भी सूखा चारा जरूरी

बरसीम रबी मौसम की अहम चारा फसल, बढ़ जाएगा गाय का दूध

भोपाल। जागत गांव हमार

दुधारू पशु को उसके शरीर के भार का 2.5 से 3.5 प्रतिशत भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, एक भैंस को 30 किलोग्राम और गाय को 25 किलोग्राम प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें दाना राशन या कंसंट्रेट भी शामिल है। इसमें 60 प्रतिशत गीला और 40 प्रतिशत सूखा चारा हो। कुल हरे-गीले चारे में से 25 प्रतिशत दलहनी प्रजातियों से और 75 प्रतिशत घास से हो। हरा चारा अधिक होने पर भी सूखा चारा जरूरी है। केवल हरा चारा खिलाने से पशु की वृद्धि और दूध की उपज और गुणवत्ता प्रभावित होती है। धान के पुआल (पैरा) को सूखे चारे के रूप में प्रयोग न करें। इसमें ऑक्सालिक एसिड की मात्रा जानवर के शरीर से कैल्शियम को खत्म कर देगी। दलहनी फसलों में 15 से 21 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है जिसके खिलाने से पशुओं के दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है।

बरसीम बरसीम पशुओं को पौष्टिक आहार प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण हरा चारा वाली फसल है। इसकी खेती रबी ऋतु में पूर्ण सिंचित अवस्था में की जाती है। इसके पौधे की बढ़वार काफी तेज होती है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी खेती करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। बरसीम को खिलाने से पशुओं के दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अधिक उत्पादन होने पर हरा चारा को 'हे' अथवा साइलेज बनाते है, जो चारे की कमी होने के समय उत्तम पशु आहार होता है।

भूमि का चुनाव दोमट मिट्टी और जिन मिट्टियों में जल धारण क्षमता अच्छी होती है। बरसीम सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। सर्वोत्तम है हल्की भूमि में इस फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है।

खेत की तैयारी एक या दो बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और पाटा लगाकर भूमि को समतल करें। एक हेक्टेयर खेत में लगभग 20 क्यारियां बनाने से सिंचाई में सुविधा होती है।

खाद और उर्वरक

20 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर की दर से बोने से पूर्व खेत में बिखेर कर अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। बोवनी के 15-20 दिन बाद यदि पौधे पीले व कमजोर दिखें तो खड़ी फसल में 10-12 किलो यूरिया का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करें।

बोवनी का समय व तरीका

बरसीम फसल की बोनी मध्य अक्टूबर से मध्य नवम्बर में करना सबसे उचित है। पहली विधि में सुविधाजनक आकार की क्यारियां बनाएं (जो पानी को रोक सकें), सिंचाई करें और खड़े पानी में बीज छिड़काव करें। ध्यान रखें कि खेत में पानी की सतह 5 सेंमी से अधिक न रहे। दूसरी विधि में बीज को खेत में छिड़क कर बोवनी करें फिर सिंचाई करें। ध्यान रखें की सिंचाई का पानी तेज गति से ना बहे नहीं तो बीज पानी के बहाव की दिशा में इकट्ठा हो जाएगा।

सिंचाई

पहली सिंचाई बोवनी के 5 से 6 दिन बाद करें, इसके बाद आवश्यकतानुसार 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। मार्च के महीने से सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल पर करें। कटाई के बाद सिंचाई आवश्यक रूप से करें। इस फसल के पूरे जीवन काल में कुल 13 से 15 सिंचाई की आवश्यकता होती है।

कटाई प्रबंधन

बरसीम हरे चारे की बहू कटाई वाली फसल है। पहली कटाई बुवाई के 50 से 55 दिन पर करें। तत्पश्चात 25 से 30 दिन के अंतर पर कटाई करें। पौधों को जमीन से 8-10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटें।

उपज से अतिरिक्त आय

मध्य अक्टूबर में बोई गयी फसल से 5-6 कटाई में लगभग 900 से 1000 क्विंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। बोवनी में विलंब होने से उपज में कमी आती है। पहली कटाई में समय अधिक लगता है, और हरे चारे का उत्पादन भी कम प्राप्त होता है। अतः चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए बोवनी करते समय बरसीम के बीज में 2 किलोग्राम सरसों या 10 किलोग्राम जई का बीज प्रति हेक्टेयर मिलाकर बोने से पहले कटाई के चारा उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि बरसीम के साथ सरसों या जई चारा, अतिरिक्त प्राप्त होता है। तथा बाद में बरसीम के उत्पादन में कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है।

बीज उत्पादन

बरसीम का बीज तैयार करने के लिए हरा चारा की कटाई मार्च प्रथम सप्ताह तक ही करें इसके बाद फसल को बीज उत्पादन के लिए छोड़ दें इस प्रकार 3-4 कटाई द्वारा 400-500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त होता है। साथ-साथ 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज का उत्पादन प्राप्त हो जाता है।

बीज दर व उपचार

20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का उपयोग करें। कासनी (चिकोरी) की समस्या से निजात पाने के लिए बीज को 5 प्रतिशत नमक के घोल वाले पानी में डुबाएं। कासनी का बीज हल्का होने के कारण पानी की सतह पर आ जाता है, इसे निकाल कर नष्ट कर दें। फिर बरसीम के बीज को नमक के घोल वाले पानी से निकाल कर 2-3 बार शुद्ध पानी से धोएं। एक किलो बीज में एक ग्राम कार्बेंडाजिम तथा 2 ग्राम थायरम से बीज उपचार करें, इससे मृदा में उपस्थित फफूंदी जनक रोग नहीं आएगी और अच्छा अंकुरण होगा। इसके बाद 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें।

बीमा कंपनी के दावे खारिज

कृषि मंत्रालय ने खरीफ-2021 का फसल बीमा जारी करने का दिया आदेश

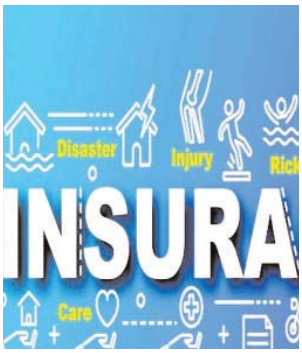

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

राजस्थान के बाड़मेर जिले में खरीफ-2021 का फसल बीमा, बीमा कम्पनी की अपील के कारण काफी समय से लंबित है। पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत जांच करवाने के उपरांत उक्त अपील को स्पष्ट तौर पर खारिज करते हुए कम्पनी को बीमा राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कम्पनी द्वारा दोबारा अपील लगाने के कारण बीमा क्लेम का निष्पादन नहीं हो सका। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बीमा कंपनी द्वारा पेश किए गए दावे और तर्क को हमने खारिज कर दिया है और कृषि मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने अंतिम आदेश और दिशा निर्देश जारी किया है। इसके बाद अब जल्द ही किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। बीमा कम्पनी द्वारा बार-बार गलत तथ्यों के आधार पर अपील लगाकर किसानों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है. भारत सरकार द्वारा इस पर पुनः संज्ञान लेते हुए बीमा कम्पनी की अपील को पूरी तरह खारिज करते हुए कम्पनी को शीघ्रातिशीघ्र किसानों के फसल बीमा का भुगतान करने के अंतिम आदेश और दिशा निर्देश दिए गए हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भारत सरकार किसानों के हक को लेकर संवेदनशील है और किसी भी स्थिति में उनके हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने देगी। आशा है कि बीमा कम्पनी अपनी हठधर्मिता छोड़कर भारत सरकार के निर्देशानुसार स्पष्ट व सही तकनीकी तथ्यों के आधार पर शीघ्र ही क्षेत्र में लम्बित बीमा क्लेम को जारी करेगी, इसको लेकर अंतिम आदेश जारी कर दिया गया है।

देश के हर किसान तक पहुंच का लक्ष्य होगा साकार

अब पीओपी पोर्टल के साथ सूचनाएं भी देगा कृषिफाई

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

किसानों की सोशल नेटवर्किंग साइट कृषिफाई का इलेक्ट्रोनिक-राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म (पीओपी) पोर्टल के साथ समायोजन कर लिया गया है। ई-एनएएम एक भारतीय व्यावसायिक कृषि पोर्टल है जो किसानों, व्यापारियों और बिचौलियों के लिए कृषि से संबंधित सामग्रियों की खरीद-परोख्त और खेतीबाड़ी में सलाह के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। अब कृषिफाई के एकीकरण के साथ ये किसानों के लिए सलाहकार की भूमिका भी निभाएगा। एक सेवा प्रदाता के रूप में कृषिफाई अपने सोशल नेटवर्क पर एक करोड़ से अधिक किसानों को जोड़ चुका है। कृषिफाई का ई-एनएएम के साथ विलय होने पर अब इसकी पहुंच देश के 14 करोड़ किसानों तक होगी। सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ किसानों को खेती और फसल सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए तुरंत समाधान देते हैं। ई-एनएएम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद देश के किसानों को वित्तीय साक्षरता, सरकारी योजनाएं और बाजार की अंतदृष्टि समझने के लिए प्रासांगिक जानकारी साक्षा की जाएगी। यह किसानों और कृषि व्यवसाय से जुड़े पेशेवरों के लिए एक पुल का कार्य करेगा। गुरुग्राम स्थित कंपनी कृषिफाई के सीईओ और सह-संस्थापक राजेश रंजन इस विलय पर कहना है कि यह निर्णय हमें देश के लाखों किसानों के लिए सूचना की खाई को पाटेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट का ई-एनएएम पोर्टल के साथ विलय देश के एक बड़े वर्ग की कृषि सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के हमारे लक्ष्य को और करीब लाया है।

किसानों को मिलेगी मदद

सीईओ और सह-संस्थापक का कहना है कि कंपनी प्रबंधन का यह निर्णय देश के कृषि व्यवसाय और किसानों तक पहुंचने में मदद करेगा। ई-एनएएम का संचालन कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह एक इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा समय में खेतीबाड़ी से जुड़े व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए देश के किसानों को एक नेटवर्क से जोड़ रहा है।

लोगों का कार्यालय आने की जरूरत नहीं

समितियों का पंजीयन अब ऑनलाइन होगा

इंदौर। जागत गांव हमार

सहकारी समितियों का पंजीयन अब केवल ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से समितियों का पंजीयन करवाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि समितियों के पंजीयन के लिए विभागीय ऑन लाईन पोर्टल पर जाकर 21 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। पोर्टल पर नवीन संस्था का आवेदन करने के लिए आवेदक उल्लेखित लिंक पर जाकर स्वयं एमपी ऑन लाईन नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदक को पोर्टल पर अपना लॉग इन क्रिएट करना होगा। लॉग इन क्रिएट करने के लिए आधार से लिंक मोबाईल नंबर प्रविष्टि कर ओटीपी सत्यापन होगा। प्रस्तावित संस्था की जानकारी एवं प्रथम आवेदन की जानकारी भरकर पासवर्ड निर्मित करेगा। तत्पश्चात आवेदक का लॉगिन निर्मित हो जाएगा। अंशपूंजी का मूल्य दर्ज करके प्रस्तावित सदस्यों के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर तदर्थ कमेटी नामांकित कर दस्तावेज अपलोड कर अंशों का मूल्य एवं सदस्यता प्रवेश शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करेगा। आधार नंबर से वर्चुएल आईडी जनरेट होगा और आवेदक का ई-साईन कर आवेदन ऑनलाईन जमा करना होगा। विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 45 दिवस के भीतर आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी। कुछ कमियां होने पर पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जिसकी सूचना एसएमएस से दी जाएगी। पंजीयन पोर्टल पर आवेदन मान्य होने पर पोर्टल से ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जनरेट होगा जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर रहेंगे।

पशुपालन-डेयरी में प्रदेश को बनाया जा सकता है नंबर वन

जबलपुर। पशुपालन विभाग ने पशु अस्पतालों की हालात सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए जबलपुर के संयुक्त संचालक समेत वरिष्ठ डाक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. विनोद बाजपेयी ने कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान यहां की व्यवस्थाओं को जायजा लिया। वहीं संयुक्त संचालक कुंडम में डॉ. संजय शर्मा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के छिंदवाड़ा स्थानांतरण होने और डॉ. अच्युत दीक्षित के कटनी जिला से कुंडम आने पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विकासखंड के पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पशु सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. मायल ने कहा कि जबलपुर डेयरी के क्षेत्र में भारत देश तथा एशिया में दूध उत्पादन के लिए विख्यात है। विभाग को उत्कृष्ट कार्यों के द्वारा जनसेवा में अग्रणी रखना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर पशुधन निगम के डॉ.आरके कुर्मी, डॉ.अविनाश श्रीवास्तव, डॉ. आशीष लखेरा, डॉ. भारती जायसवाल, डॉ. नमन सिंह, डॉ. सुनील यादव मौजूद रहे।

आठ हजार किसानों ने केवायसी नहीं कराया

भोपाल में 11 हजार किसान आधार से लिंक नहीं

भोपाल। भोपाल जिले में 11 हजार से ज्यादा किसानों ने अपने बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराए हैं, जबकि 8 हजार से अधिक किसानों ने केवायसी भी नहीं कराया है। ऐसे में उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली राशि नहीं मिल सकेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ ले रहे किसानों को अपना ई-केवाइसी एवं बैंक खाता आधार से लिंक करवाना था, लेकिन 1 नवंबर तक 19 हजार से ज्यादा किसान पीछे रह गए। भू-अभिलेख अधीक्षक वंशिका इंग्ले ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे सभी किसानों को अपना ई-केवाइसी और आधार नंबर बैंक खाता से लिंक अनिवार्य है। लिंक नहीं होने की दशा में दोनों योजनाओं की किश्तों का भुगतान किसानों को नहीं किया जाएगा।

भोपाल में इतने किसान पीछे

भोपाल जिले में कुल 70 हजार किसान हैं। इनमें से बैरसिया के 7 हजार 533, हुजूर तहसील के 3 हजार 275 एवं कोलार तहसील में 342 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने अपना बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया है। इनकी कुल संख्या 11 हजार 150 है। वहीं, 8 हजार 562 ऐसे शेष किसान हैं जिन्होंने अपना ई-केवाइसी भी अभी तक नहीं कराया है।

तीतर खत्म होने की कगार पर, अगर पालन करना चाहते हैं तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा

मुर्गी पालन से भी ज्यादा मुनाफा! साल में 300 से ज्यादा अंडे देती तीतर

भोपाल। जागत गांव हमार

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच मुर्गी पालन का चलन ज्यादा है। हालांकि, एक ऐसी भी पक्षी है जिसके पालने से किसान बंपर मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल, इस पक्षी का बिजनेस करने वाले किसानों की संख्या कम है। विशेषज्ञों के अनुसार तीतर एक जंगली पक्षी है। कई लोग इसका मीट बड़े चाव से खाते हैं। इसे कई जगहों पर बटेर के नाम से भी जाना जाता है। तीतर अब खत्म होने की कगार पर हैं। अगर आप तीतर पालन करना चाहते हैं तो आपको सरकार से इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार मादा तीतर के अंदर एक साल में 300 अंडे देने की क्षमता होती है। ज्यादातर तीतर अपने जन्म के 45 से 50 दिनों में अंडे देना शुरू कर देती हैं। इसके व्यवसाय को बेहद कम वक्त में शुरू किया जा सकता है। साथ ही इससे इनकी घटती संख्या में बढ़ोत्तरी होगी और तीतर पालक को बंपर मुनाफा भी हासिल होगा। इन पक्षियों का आकार छोटा होता है। भोजन और जगह के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। निवेश की भी कम जरूरत पड़ती है। सिर्फ 4-5 तीतर को पालकर भी इसका बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तीतर का अंडा रंगीन होता है। इसमें कॉर्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और मिनिरल प्रचूर मात्रा में होते हैं। प्रति ग्राम जर्दी में 15 से 23 मिली ग्राम कोलेस्ट्राल पाया जाता है। कई तरह के बीमारियों में इसके अंडे के सेवन की सलाह दी जाती है। बाजार में तीतर के मांस की ब्रिकी आसानी से होती है। किसी भी नजदीकी मंडी में इसे आप आसानी से बेच सकते हैं। एक बटेर 50 से 60 रुपए तक आसानी से बिक जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से बटेर या तीतर की खेती करें तो हर साल लाखों का मुनाफा हो सकता है।

पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु से अधिक मात्रा में धान खरीदा

केरल-तमिलनाडु में, खरीद कार्य सितंबर से होता है शुरू

अक्टूबर तक सरकारी धान खरीदी 12% से बढ़कर 170.53 लाख टन तक पहुंची

भोपाल/नयी दिल्ली। जागत गांव हमार

सरकार की केंद्रीय पूल के लिए धान खरीद चालू खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के अक्टूबर महीने तक 12 प्रतिशत बढ़कर 170.53 लाख टन हो गई है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु से अधिक मात्रा में धान खरीदा गया है। आमतौर पर धान खरीद का काम, अक्टूबर से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के तुरंत बाद शुरू होता है। हालांकि, दक्षिणी राज्यों खासकर केरल और तमिलनाडु में, यह खरीद कार्य सितंबर से शुरू होता है। सरकार का लक्ष्य खरीफ विपणन सत्र 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) में 771.25 लाख टन धान की खरीद करना है। पिछले खरीफ विपणन सत्र में वास्तविक खरीद रिकॉर्ड 759.32 लाख टन की हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 खरीफ विपणन सत्र के 31 अक्टूबर तक कुल धान खरीद बढ़कर 170.53 लाख टन हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 152.57 लाख टन थी। कुल खरीद में से, लगभग 107.24 लाख टन धान पंजाब से अक्टूबर के अंत तक खरीदा गया है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह खरीद 99.12 लाख टन रही थी।

यूपी अभी पिछड़ा

हरियाणा से एक साल पहले इसी अवधि में 48.27 लाख टन के मुकाबले इस बार 52.26 लाख टन खरीदा गया है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में इस खरीफ विपणन सत्र के अक्टूबर-अंत तक धान की खरीद कम यानी 33,668 टन रही, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 83,766 टन रही थी। उत्तराखंड में खरीद पिछले साल के 2.35 लाख टन की तुलना में इस बार 2.46 लाख टन से थोड़ी अधिक रही है।

जम्मू-कश्मीर निकला आगे

जम्मू-कश्मीर में खरीद एक साल पहले की समान अवधि के 6,756 टन के मुकाबले अधिक यानी 11,170 टन की हुई। हिमाचल प्रदेश में हालांकि, इस सत्र के अक्टूबर तक धान की खरीद कम यानी 6,111 टन रही है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 7,374 टन रही थी। आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में इस खरीफ विपणन सत्र के अक्टूबर-अंत तक लगभग 7.90 लाख टन धान की खरीद की गई है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में 1.77 लाख टन धान खरीद की गई थी।

केरल में कम हुई खरीदी

केरल में अक्टूबर के अंत तक 4,159 टन धान की खरीद हुई है, जो साल भर पहले की इसी अवधि के 5,203 टन धान की खरीद से कम है। धान की खरीद सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और निजी एजेंसियों दोनों द्वारा की जाती है। धान किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाता है और कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत मांग को पूरा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।

राज्यों में घटा रकबा

धान, खरीफ (गर्मी) और रबी (सर्दियों) दोनों मौसमों में उगाया जाता है। लेकिन देश के कुल धान उत्पादन का 80 प्रतिशत हिस्सा खरीफ सत्र से आता है। कृषि मंत्रालय के पहले अनुमान के अनुसार, खरीफ सत्र 2022-23 में देश का धान उत्पादन छह प्रतिशत घटकर 10 करोड़ 49.9 लाख टन रहने का अनुमान है, जिसका कारण प्रमुख उत्पादक राज्यों, विशेषकर झारखंड में, खराब बारिश के मद्देनजर धान खेती का रकबा कम होना है।

कृषि स्थायी समिति की बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने उठाए मुद्दे

गांव में फ्री इलाज की व्यवस्था, फिर भी पशु चिकित्सक वसूल रहे पैसा

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन विभाग के द्वारा किसानों एवं पशुओं के उपचार की क्या व्यवस्था है। उपचार नि:शुल्क किया जाता है। फिर भी ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं कि पशुओं का इलाज करने के लिए पशु चिकित्सक उनसे रुपए मांगते हैं। उपचार और दवाओं के बारे में अवगत कराना चाहिए। यह जानकारी जिला पंचायत सदस्य इंदिरा अशोक मीना ने पशुपालन विभाग के डॉ. अजय रामटेके से ली। वह जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित कृषि स्थायी समिति की बैठक को सभापति के रूप में अध्यक्षता कर रहीं थीं। बैठक में उप संचालक कृषि सुमन प्रसाद परसाई ने एजेंडा रखा। सभापति द्वारा जानकारी मांगे जाने पर डॉ. आजम रामटेके ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का इलाज नि:शुल्क शासकीय डॉक्टर एवं कंपाउंडर के द्वारा किया जाता है किसी भी प्रकार के रुपए नहीं लिए जाते हैं। प्राइवेट दवाएं या कुछ नीम राशि जमा कर दवाएं दी जाती है उनकी राशि ली जाती है। शिकायत आई है, इसे हम गंभीरता से लेते हैं आगे ध्यान रखेंगे। बैठक में एसके, शर्मा एसएडीओ फंदा, पीएस गोयल बैरसिया, बीएफ रघुवंशी, विपणन बोर्ड, भोपाल कोऑपरेटिव बैंक आदि विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

सदस्यों ने जताई नाराजगी

जिला पंचायत सदस्य देव कुंअर अनिल हाड़ा ने पशुपालन विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हुए पूछा कि भोपाल जिला ग्रामीण में कितने तालाब पंचायत के अधीन हैं और किस-किस तालाब में मछली पालन किया जाता है। मोहन सिंह जाट उपाध्यक्ष एवं सदस्य बिजिया विनोद राजोरिया ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को पलेवा के लिए लाइट नहीं मिल रही है। किसान डीएपी एवं मजबूरियां खाद के लिए रात जागरण कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसानों को समय पर खाद वितरण क्यों नहीं हो रहा है। रात-दिन जाकर बिजली एवं खाद के लिए किसान जागरण कर रहा है जवाबदेह कौन है। कृषि विभाग के द्वारा किसानों को कृषि यंत्र घटिया किस्म के दिए जा रहे हैं। उन पर कितनी सब्सिडी है। कृषि विभाग के द्वारा कृषि यंत्र कहां से क्रय किए जाते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी 7 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाए।

कुशवाह ने साझा की जानकारियां

उद्यानिकी विभाग के अधिकारी बीएस कुशवाह ने सभी सदस्यों को विस्तार से उद्यानिकी विभाग की जानकारियां समझाइए। उन्होंने बैठक में बताया कि बागवानी यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत लॉटरी द्वारा अधिकतम 20 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के लिए कृषकों का चयन किया गया। सदस्यों ने पर्ची उठाकर चयन करते हुए इसके अंतर्गत अनुदान के आधार पर दो श्रेणियों में तृषा को का चयन किया गया। तीन ट्रैक्टर के लिए बड़े कृषक जिनको प्रति यंत्र 75000 रुपए का अनुदान है। एसटीएससी अनुसूचित जनजाति लघु सीमित एवं महिला कृषक के लिए 100000 रुपए राशि अनुदान है। इनको चार ट्रैक्टर चयनित किसानों को दिए जाएंगे। जो भी चयनित किसान ट्रैक्टर नहीं लेते हैं तो उनकी जगह वेटिंग के किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा।

---

11 किस्त की राशि ली, अब 22 हजार की वसूली होगी

अपात्र किसानों से हो रही 5.1 करोड़ रुपए पीएम सम्मान निधि की वसूली

अशोकनगर। जागत गांव हमार

जिले में एक लाख 28 हजार किसान पीएम सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से करीब 5 हजार 698 अपात्र किसान हैं, जो इस सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। नए नियम आए तो इन अपात्र लोगों से अब जो राशि जमा कराई गई थी उसको वसूला जा रहा है। जिले में करीब 5.1 करोड़ की राशि फर्जी खातों में जमा हो गई है। जिन लोगों के बैंक खातों में राशि भेजी गई थी उसकी अब वसूली की जा रही है। 84 लाख 50 हजार रुपए के आसपास वसूली अब तक हो भी चुकी है।

एक दिसंबर 2018 से शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत किसानों के खातों में हर चार माह में 2000 रुपए की किश्त जमा की जाती है। यानी साल भर में 6000 रुपए जमा होते हैं। योजना के तहत किसानों को अब तक 12 किस्त मिल चुकी है।

लेकिन इस योजना की शुरुआत में तो सभी किसानों को जोड़ दिया गया। लेकिन बाद में जब बाद में इस योजना के नियम आए तो फिर ऐसे लोगों को खोजा गया जो नियम के अनुसार अपात्र हैं। पूर्व में जिन अपात्र लोगों के खातों में यह राशि पहुंच गई अब उनको नोटिस जारी करते हुए राशि की वसूली की जा रही है।

पटवारी को वसूली का मिला जिम्मा

वसूली के लिए राजस्व विभाग द्वारा पटवारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस योजना में जिन लोगों को अपात्र माना गया उनमें फेक अकाउंट होल्डर्स सरकारी नौकरी, आयकर भरने वाले और एक ही परिवार के दो-दो लाभार्थी हैं। इनमें से सबसे अधिक संख्या एक ही परिवार के दो-दो लाभार्थी की है। इन सभी लोगों से राशि की वसूली की जा

वापस नहीं की तो भेजे नोटिस | जिले में कई ऐसे परिवार है जिनमें पति-पत्नी या एक ही परिवार के एक से अधिक लोगों ने इस सम्मान निधि का लाभ लिया। वहीं योजना में कई किसान इनकम टैक्स भरने वाले भी है। ऐसे लोगों ने जब उक्त राशि को वापस नहीं किया तो राजस्व विभाग ने नोटिस भी जारी किए। वहीं जो किसान बचे हुए हैं उन्हें भी नोटिस भेजने की तैयारियां चल रही हैं।

एक अपात्र से 22 हजार वसूलेंगे | अपात्र किसानों से राशि वसूलने की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया में ऐसे किसान जिन्होंने योजना के तहत 11 किस्त की राशि ली है उनके खातों से 22 हजार रुपए की वसूली होगी। हालाकि अभी भी इस योजना में कई ऐसे किसान छूट रहे हैं जो अपात्र हैं, लेकिन उनके पास न तो नोटिस पहुंचा है और न ही उनके नाम इस योजना से हटे हैं। ऐसे किसानों के नाम भी खोजने की प्रक्रिया चल रही है।

जिले की प्रमुख तहसीलों की स्थिति

तहसील	राशि	किसान संख्या
मुंगावली	13508000	1775
अशोकनगर	12802000	1459
ईसागढ़	10474000	1200
शाढौरा	7628000	932
चंदेरी	5638000	595
अन्य	50000	07

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंडला में कहा

किसान अन्न के साथ अब ऊर्जादाता भी बनेगा

भोपाल। जागत गांव हमार

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मप्र में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। मध्यप्रदेश को निरंतर कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अब मध्यप्रदेश कृषि उत्पादों का निर्यात भी करने लगा है। किसान अन्नदाता के साथ अब ऊर्जादाता भी बनेगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मंडला में मंडला और डिंडोरी जिले के लिए 1261 करोड़ रुपए लागत की 5 सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मंडला में प्रकृति का निवास है, यह रानी दुर्गावती की भूमि है तथा यहां कान्हा जैसा विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। जनजातीय कार्यों के विकास के लिए सड़कें अत्यंत जरूरी हैं। गडकरी ने देशभर में ऊर्जा के क्षेत्र में परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई नई परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मध्यप्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि मंडला, डिंडोरी एवं अन्य जनजातीय क्षेत्रों में बांस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। बांस से भविष्य में इथेनॉल का निर्माण होगा, जिससे परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों के लिए ऊर्जा पैदा की जा सकेगी।

अब पराली से बनेगा बायो-बिटुमन

गडकरी ने कहा कि अगले दो-तीन महीनों में एक नई तकनीक लाई जाएगी, जिसमें ट्रैक्टर में मशीन लगाकर खेत में पराली का इस्तेमाल बायो-बिटुमन बनाने में किया जाएगा। किसान अन्नदाता होने के साथ ऊर्जादाता भी बन सकते हैं। साथ ही वे बायो-बिटुमेन बना सकते हैं, जिसका उपयोग सड़क बनाने में किया जा सकता है। इसके लिए मैंने एक नई तकनीक की रूपरेखा पेश की है, जिसे हम दो से तीन महीनों में जारी करेंगे।

सोयाबीन उत्पादन बढ़ा

गडकरी ने जल, जमीन और जंगल के समुचित उपयोग द्वारा विकास का नया मॉडल लागू करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति एकड़ सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा है और किसानों को उपज का उचित मूल्य मिला है।

किसानों को बार बार बेचने की धोखाधड़ी से मिलेगा छुटकारा

स्वामित्व सर्वे पूरा होने के बाद आटो मोड में जनरेट होगा पिन

मप्र में आधार की तरह हर जमीन का होगा 'आल पिन'

ग्वालियर। जागत गांव हमार

जिस तरह आम आदमी पहचान आधार कार्ड के अंकों से होती है उसी तरह अब जल्द हर जमीन का भी आल पिन होगा। यह एक तरह से जमीन की पहचान का कोड होगा। जमीन का पूरा रिकॉर्ड बताने के साथ साथ यह बदला नहीं जा सकेगा। इस तरह जमीनों की धोखाधड़ी करने वालों को सबसे बड़ा झटका लगेगा। लैंड रिकॉर्ड और राजस्व तत्काल इस आल पिन के माध्यम से जमीन की पूरी कुंडली निकाल सकेंगे। लैंड रिकॉर्ड की ओर से चल रहे गांवों में चल रहे जमीनों का स्वामित्व सर्वे पूरा होते ही आटो मोड में यह जनरेट हो जाएंगे। शहर और गांव दोनों की जमीन के लिए यह आल पिन जनरेट होंगे। हाल ही में भारत सरकार के संयुक्त सचिव सोनमणि बोरा ग्वालियर तीन दिन के प्रवास पर आए थे। इस दौरान उन्होने भूमि सुधार व आधुनिकीकरण को लेकर आफिस से लेकर मैदान तक पूरी व्यवस्थाएं देखीं थीं। इसी दौरान ग्रामीण क्षेत्र में जाकर ड्रोन सर्वे जो स्वामित्व सर्वे के तहत किया जा रहा है, इसे देखा था। यहीं उनकी टीम के जरिए अधिकारियों को बताया गया कि स्वामित्व सर्वे पूरा होते ही हर जमीन का आटोमेटिक आल पिन जनरेट हो जाएगा जिससे हर जमीन की अलग नंबरों के जरिए पहचान होगी।

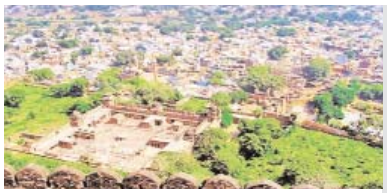

बार-बार जमीन बिक्री से मिलेगी मुक्ति

जमीनों की धोखाधड़ी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इस पर रोक लगाने के लिए यह जमीनों की आल पिन की व्यवस्था कारगर साबित होगी। ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं पूरे प्रदेश में जमीनों की धोखाधड़ी राजस्व से लेकर पुलिस के लिए सिरदर्द बनी रहती है। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा मामले जमीनों की धोखाधड़ी के ही सामने आते हैं।

मालिक एक तब भी जमीन का होगा अलग नंबर| एक व्यक्ति के पास अगर अलग अलग जगह जमीनें हैं तो भी उसे हर जमीन का अलग अलग आल पिन मिलेगा। मालिक एक ही रहेगा और अगर एक जमीन का बड़ा हिस्सा है और कई भाई या पार्टनर हैं तो सबके पास अपने अपने स्वामित्व की जमीन का अलग कोड ही होगा।

अब ग्वालियर में अब यह भी होगा

- लैंड रिकॉर्ड का जो रिकार्ड रूम है उसमें साल में एक बार माल ड्रिल कराई जाएगी जिससे आपात स्थिति में व्यवस्थाओं को चेक किया जा सके।
- लैंड की पूरी जानकारी वाली जो हार्ड डिस्क है उसे एक बार साल में चलाकर देखा जाएगा और चेक किया जाएगा कि कहीं जमीनों का डाटा लीक या कहीं भेजा तो नहीं जा रहा है।
- जमीनों के डिजिटल नक्शे के साथ साथ जो मैन्युअल नक्शे रखे हैं उसका रखरखाव ठीक से किया जाए और समय समय पर इसे चेक भी किया जाए। इसके साथ ही जो बस्ते रखे गए हैं उनकी भी जांच की जाएगी।

गांवो में वर्तमान में स्वामित्व सर्वे चल रहा है और यह पूरा होते ही जमीनों का आल पिन कोड जनरेट हो जाएगा। आटोमोड में यह प्रक्रिया होगी। इससे जमीनों की बार बार बिक्री व धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लग सकेगी। रिकॉर्ड रूम में साल में एक बार माक ड्रिल भी होगी।
शिवानी पांडेय, प्रभारी अधीक्षक,भू-अभिलेख, ग्वालियर

-मुख्यमंत्री की सभी कलेक्टरों से दो टूक

किसानों को आसानी से उपलब्ध हो खाद

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को आसानी से खाद मिले। वितरण केंद्र के पास टेंट, बैठक व्यवस्था और पेयजल का प्रबंध रहे। उपलब्धता के बावजूद वितरण व्यवस्था की किसी कमी के कारण किसान को परेशानी नहीं आना चाहिए। किसान को लाइन न लगाना पड़े, उसका समय और ऊर्जा जाया न हो, इसके लिए कलेक्टर पूरी व्यवस्था पर निगरानी रखें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, न ही आने वाले समय में कमी रहेगी।

वे नियमित रूप से केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से सम्पर्क में हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश को सदैव आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। बैठक में हरदा जिला में प्रशासन द्वारा खाद वितरण की बेहतर व्यवस्था पर चर्चा हुई। कलेक्टर हरदा ने बताया कि जिले में एक्स्ट्रा काउंटर व्यवस्था, विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय, वितरण केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के साथ ही डिफाल्टर किसान सहित सभी के लिए खाद के प्रबंध आवश्यतानुसार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अन्य जिलों में ऐसे ही व्यवस्थित उपाय कर किसानों की शिकायत शून्य करने के निर्देश दिए।

इन जिलों खाद की किल्लत

मुख्यमंत्री ने सतना, दमोह, सागर, छतरपुर, नीमच नर्मदापुरम, देवास और इंदौर जिलों के कलेक्टर्स से खाद की उपलब्धता, वितरण केंद्र संख्या, वितरण व्यवस्था और इस माह की संभावित मांग के अनुरूप आपूर्ति के प्रबंध के संबंध में बातचीत कर निर्देश दिए।

कलेक्टरों को निर्देश

- किसी भी जिले में किसानों को लाइन न लगानी पड़े।
- प्रदेश के हर जिले में खाद वितरण व्यवस्था सुचारू रहे
- किसानों को अधिक दूरी से खाद लेने न आना पड़े।
- आवश्यक हो तो अतिरिक्त अमला इस कार्य में लगाएं।
- जरूरत हो तो वितरण के लिए अतिरिक्त केंद्र शुरू करें।

स्व-सहायता समूहों की 4500 महिलाओं की भागीदारी

प्रदेश में बांस रोपण में 5 गुना हुई बढ़ोतरी

भोपाल। जागत गांव हमार

वन उत्पादों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों से आजीविका के अवसर बढ़ाये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश राज्य बाँस मिशन द्वारा 4500 से ज्यादा महिलाओं को स्व-सहायता समूह के माध्यम से बाँस-रोपण से सीधे जोड़ा गया है। वन मंत्री डॉ. कुवर विजय शाह ने बाँस मिशन में सहयोगी बनी महिलाओं के प्रयासों की सराहना की है।प्रदेश में बांस रोपण में 5 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में 2623 हेक्टेयर में बाँस रोपण किया गया था, जो इस वर्ष बढ़ कर 13 हजार 914 हेक्टेयर हो गया है। मनरेगा स्कीम में 4511 हेक्टेयर में बाँस-रोपण किया जा चुका है। इससे 4 हजार 500 से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है, जो स्व-सहायता समूह की सदस्य है। बाँस का उत्पादन शुरू होते ही इन परिवारों की आय में वृद्धि होगी और यह परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कृषि एवं वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बाँस-रोपण किया जा रहा है। बीते 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में 18 हजार 781 हेक्टेयर क्षेत्र और मनरेगा के अलावा विभागीय योजनाओं में 14 हजार 862 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बाँस का रोपण किया गया। इस प्रकार कुल 33 हजार 643 हेक्टेयर में बाँस रोपण का काम हो चुका है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

- जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।
- समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।
- ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)